

राजस्थान सरकार
सांख्यिकीय न्याय एवं अधिकारिता विभाग

58

सं. 11(1) आदेश/सा.सा.वि./08/5724-68 जयपुर, दि. 11/2/49
सांख्यिकीय विभाग

विषय- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे अनेक प्रकरण आये गये हैं, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र संबंधित प्रावधान अधिनियमों द्वारा दिये गये को ध्यान में रखकर जारी नहीं किये जाते हैं। परिणामस्वरूप अनेक वैधानिक जटिलताएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

विभाग के संपर्कगत सं. 22472-48 दि. 4.4.90, 43568-638 दि. 13.11.2000 एवं 0454-83 दि. 21.2.04 आदि आदेशों को ध्यान में रखते हुए जाति प्रमाण-पत्र जारी करने एवं जाति प्रमाण-पत्रों का भ्रष्टाचार संबंधी अनुसंधान विचारते गये थे। तत्परिणाम स्वरूप जाति प्रमाण-पत्रों में अन्यायपूर्ण धारणा नहीं दिया जा रहा है। अतः आपको कुछ उच्च पदों की प्रतियाँ भेजकर अनुसंधान किया जाता है कि आप प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व संपर्क विभाग, अन्य अधिकार एवं शक्ति की आवश्यकता एवं विवरणों का ध्यान रखते हुए जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के विचार प्रकट करें। प्रावधानों के अंतर्गत ही जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के विचार प्रकट करें।

सुखन संदर्भ अनुसूचित जाति व जनजाति की वर्गीकरण प्रणाली सूची संशोधन कर प्रेषित की जा रही है। जाति प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व जाति कार्य प्राधिकारियों से प्रादेशिक अधिकारियों की रिपोर्ट एवं उच्च सूची का भी समुचित अध्ययन कर स्वयं के रूप में संपुष्ट हो सके। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम 1978 के बाद राज्य में जातियों की सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन (change) नहीं हुआ है।

आपका आभारपूर्वक धन्यवाद

भवदीय
शासन उप सचिव